

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 19 अक्टूबर 2026 वर्ष-9, अंक-258 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

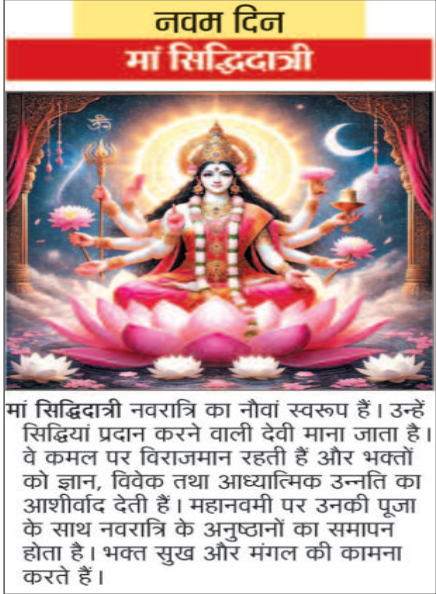
Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1



मां सिद्धिदात्री नवरात्रि का नौवां स्वरूप है। उन्हें सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और भक्तों को ज्ञान, विवेक तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देती हैं। महानवमी पर उनकी पूजा के साथ नवरात्रि के अनुष्ठानों का समापन होता है। भक्त सुख और मंगल की कामना करते हैं।

संक्षिप्त

समाचार

यूपी में फॉर्म-7 पर गलत जानकारी दी तो होगी जेल

● चुनाव आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए गलत जानकारी देना भारी पड़ सकता है। मुख्य निर्वाचन



अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रारों को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फॉर्म-7 के तहत मिलने वाली आपत्तियों की जांच निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक की जाए। जांच में आपत्ति गलत या मनगढ़ंत पाए जाने पर संबंधित आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

काशी नरेश का हाथी बेकाबू महावत को उठाकर पटका

● रामलीला से पहले खंभे उखाड़े दीवारें और दुकानें तोड़ीं

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी की मशहूर रामलीला में आया हाथी अचानक बेकाबू हो गया। इधर-उधर भागने लगा। आसपास रखी चीजों को सूंड से उठाकर फेंकने लगा।



बिजली के खंभे तोड़ दिए। दीवारें और दुकानें भी तोड़ दीं। यह देखकर आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागे। महावत ने काबू में करने की कोशिश की तो हाथी ने उसे सूंड से उठाकर पटका दिया। पैरों से भी कुचलने की कोशिश की। उसे 50 टांके लगे हैं। घटना पंचवटी मैदान में रविवार सुबह 10.30 बजे की है।

सीएम योगी ने दुर्गा पूजा और रामलीला पंडालों की सुरक्षा जांच के लिए निर्देश

कोलकाता भगदड़ के बाद यूपी में हाई अलर्ट

लखनऊ (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से हुई जनहानि के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए प्रदेशभर में हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही दुर्गा पूजा और रामलीला पंडालों में सुरक्षा के पख्खा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस कमिश्नरों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों में स्थापित पंडालों का तत्काल व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। निर्देशों का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना और अव्यवस्था की आशंका को रोकना है।

फायर सेपटी और बिजली व्यवस्था की होगी जांच

सीएम योगी ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर सभी पंडालों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों और निर्धारित मानकों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। पंडालों में कपड़े, लकड़ी और सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।

प्रवेश और निकास के रास्तों पर विशेष ध्यान

कोलकाता में भीड़ के दबाव के बीच हुई भगदड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा और रामलीला पंडालों में प्रवेश तथा निकास की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए प्रवेश और बाहर निकलने के रास्ते अलग-अलग और पर्याप्त चौड़े होने चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक पंडाल में आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में स्पष्ट इमरजेंसी एजिट मार्ग बनाए रखने को कहा गया है। इससे भीड़ बढ़ने की स्थिति में लोगों की आवाजाही व्यवस्थित रखने और हालात को समय रहते नियंत्रित करने में मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कागजी रिपोर्टें पर निर्भर रहने के बजाय खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं।

ग्वालियर में ट्रक ने 41 को कुचला, 15 की मौत

ग्वालियर (एजेंसी)। ग्वालियर में शनिवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने 41 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। दो पुलिसकर्मी समेत 26 लोग घायल हैं। चीनौर रोड पर ढलान के पास अनियंत्रित हुए धान से भरे ट्रक ने सड़क किनारे मौजूद श्रद्धालुओं और दुकानों को कुचल दिया। इसके बाद ट्रक मंदिर के प्रवेश द्वार और बाहरी दीवार

● शीतलामाता मंदिर में दर्शन के लिए खड़े थे लोग

से जा टकराया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घायलों में दो पुलिसकर्मी भी हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चिख-पुकार मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम राहत-बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यह हादसा शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1.30 बजे चीनौर रोड पर ढलान के पास हुआ। बताया जा रहा है कि नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतला माता मंदिर के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान धान से भरा एक ट्रक वहां पहुंचा और चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे मौजूद श्रद्धालुओं और दुकानों को कुचलता हुआ मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया।



मृतकों के परिजनों को 4 लाख, घायलों को भी आर्थिक मदद

हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हादसे में घायल सभी लोगों का निःशुल्क उपचार कराया जाए, ताकि उन्हें समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। दुर्घटना से प्रभावित परिवार ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर के बताए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्री ऐंदल सिंह कंधाना और मंत्री राकेश शुक्ला को ग्वालियर पहुंचने के निर्देश दिए।



अब महाराष्ट्र के बीड में भीषण सड़क हादसा

तेज रफ्तार बस और कार की टक्कर में पांच लोगों की मौत, सीएम ने दिए जांच के निर्देश

पुणे/बीड (एजेंसी)। कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ और ग्वालियर में बेकाबू ट्रक द्वारा लोगों को कुलचने की घटना के बाद महाराष्ट्र के बीड में भयावह एक्सीडेंट सामने आया है। यहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस और कार की टक्कर में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार को लोग कार

से तुलजापुर जा रहे थे। इस हादसे में पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीड जिले के माजलगांव इलाके में शिंदेवाड़ी फाटा के पास एक राज्य परिवहन बस और कार की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

सीजेपी प्रोटेस्ट में हिंदू विरोधी नारे, दिल्ली से गोवा तक ऐक्शन



300 से ज्यादा के खिलाफ एफआईआर, कार में लाटियां ले जा रहे 2 गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉन्ग्रेस जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के बीच दिल्ली से गोवा तक ऐक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के साथ एफआईआर हुई हैं तो वहीं, गोवा में भी 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस बीच सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी के आरोप लगे हैं। घटना गोवा में हुई है, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री खुद ऐक्शन मोड में आ गए हैं। इधर, गोवा पुलिस ने 11 अक्टूबर को पणजी में कॉन्ग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने ऐसे नारे लगाए, जिसे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस इंसपेक्टर विजयकुमार चोडनकर ने बताया कि सीजेपी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदुत्व मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए।

डराने की कोशिश, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे: दीपके

सीईसी के इस्तीफे की मांग पर डटे सीजेपी प्रमुख

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉन्ग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज सीरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों के आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और तय करेंगे कि इस लड़ाई को किस दिशा में ले जाना है। दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारियों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। कॉन्ग्रेस जनता पार्टी के नेता



की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उनकी रिहाई के लिए अर्जी और जमानतदारों के दस्तावेज जमा करा दिए गए हैं, और पुलिस द्वारा इनका सत्यापन किया जा रहा है।

मणिपुर में कुकी और नगा समुदायों के बीच गोलीबारी

1 व्यक्ति की मौत, 4 घायल, हिंसा में 15 घर जले

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के कामजोंग जिले के चसाद गांव में शनिवार को कुकी और नगा समुदायों के हथियारबंद समूहों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक मुजुवा और व्यामर के ताराखुल उखावदी थे। हालांकि, इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हिंसा के बाद कुकी समुदाय के 15 घरों में आग लगा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी से अब तक 50 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।



दूसरी घटना में तीन नागरिकों को गोली लगी

दूसरी घटना कामजोंग जिला मुख्यालय में हुई, जहां नगा समुदाय के तीन नागरिकों को गोली लगी। नगा विलेज गार्ड की ईस्टर्न कमांड के मुताबिक, घायलों की पहचान टी. विथुंग, एस. मालुंग और एम. शिथुंग के रूप में हुई है। तीनों नागरिक रक्षा स्वयंसेवक हैं।

वायुसेना का नया संचार कवच 'जीसैट-7सी'

2563 करोड़ रुपए का सैटेलाइट, पूरी तरह है स्वदेशी



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना की संचार क्षमता मजबूत करने के लिए देश में जीसैट-7सी सैन्य उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 2,563 करोड़ रुपए का करार किया। इसके तहत उपग्रह का डिजाइन, विकास और निर्माण किया जाएगा। इस उपग्रह की सबसे बड़ी खासियत दूर तक सुरक्षित संचार उपलब्ध कराने की क्षमता होगी। इससे लड़ाकू विमानों, निगरानी विमानों, मानवबलित विमानों और जमीन पर मौजूद सैन्य केंद्रों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी। सामान्य रेडियो संचार की पहुंच से बाहर होने पर भी उपग्रह के जरिए

अंतरिक्ष में संचार केंद्र का काम करेगा सैटेलाइट

जीसैट-7सी अंतरिक्ष में संचार केंद्र की तरह काम करेगा। यह विमानों और जमीन पर मौजूद सैन्य इकाइयों के बीच संपर्क बनाने में मदद करेगा। जब विमान सामान्य रेडियो की सीधी पहुंच से दूर होंगे, तब उपग्रह के जरिए संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकेंगे।

सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हो सकेगा। भारतीय वायुसेना का यह दूसरा समर्पित संचार उपग्रह होगा।

मुझ पर केस किया तो मामला लीगल हो जाएगा

● राहुल बोले-हर राज्य में वोट चोरी की बात कहता हूं ● सीईसी ज्ञानेश कुमार जानते हैं कीमत चुकानी होगी

पणजी (एजेंसी)। राहुल गांधी ने रविवार को गोवा में कहा कि मैं हर स्टेट से कहता हूं पीएम वोट चोरी करते हैं। लेकिन मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं होता। क्योंकि, ये जानते हैं कि अगर केस हुआ तो मामला लीगल हो जाएगा और ये फंस जाएंगे। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार रात को सो नहीं पाते। पीएम और गृहमंत्री को भी नींद नहीं



गोवा में सरकार आपकी जमीन छीन रही

राहुल ने कहा- गोवा देश में सबसे सुंदर जगह है, सबसे अच्छा कल्चर है। लेकिन यहां भी सरकार आपकी जमीन छीनकर गोवा के जो बाहर के लोग हैं उनको करोड़ों में बेचती है। पहले मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान को रद्द कर दिया। इनका यही काम है कि पैसा कैसे बनाए। राहुल ने कहा- मैं हर स्टेट से कहता हूं पीएम नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं। लेकिन मुझ पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। क्योंकि, ये जानते हैं कि अगर केस हुआ तो मामला लीगल हो जाएगा और ये फंस जाएंगे।

आती। क्योंकि, वे जानते हैं कि जनता आज नहीं तो कल उनसे न्याय लेगी। राहुल कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान 'गोय राखोन यात्रा' में शामिल होने गोवा पहुंचे थे। यहां कांग्रेस की 28 दिन लंबी यात्रा का समापन हुआ है। राहुल का पिछले 4 सालों में यह पहला गोवा दौरा है। इससे पहले 2022 में वह यहां आए थे। गोवा में आने साल 2027 में चुनाव हैं।

राहुल बोले-दिल्ली में हम सरकार से जल्द निपट लेंगे

राहुल ने कहा- आप गोवा के बारे में सोचिए। दिल्ली में हम कुछ ही समय में हम पीएम मोदी, अमित शाह से निपट लेंगे। काम जारी है। एक्सपायरी डेट आने वाली है। आपने देखा है कि आजकल नरेंद्र मोदी सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि देश का युवा इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। राहुल ने कहा- पूरी दुनिया मानती थी कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नंबर वन मॉडल का था। लेकिन, आज दिल्ली में स्टूडेंट्स को ही मारा जा रहा है। हर एजुकेशनल सिस्टम में इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। हाईटेक करप्शन, जमीन का करप्शन ये यहां करते हैं। जैसे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी का मॉडल था। वैसे ही गोवा में करप्शन का मॉडल है। इसे सिर्फ कांग्रेस ही खत्म कर सकती है। राहुल ने कहा- पहले मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान को रद्द कर दिया। इनका यही काम है कि पैसा कैसे बनाए। इनका यही काम है। गोवा की जनता को लूटने का, आपकी जमीन छीनकर अरबपतियों को देने का।

सामाजिक सुरक्षा का कवच और समावेशी विकास का उजाला

(लेखक- ललित गर्ग)

किसी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन केवल उसकी आर्थिक विकास दर, विशाल औद्योगिक परियोजनाओं, आधुनिक तकनीक, विदेशी निवेश और ऊंची प्रति व्यक्ति आय से नहीं किया जा सकता। विकास की सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिले, श्रमिक को अपने भविष्य के प्रति विश्वास हो, वृद्धावस्था अभाव का पर्याय न बने और बीमारी किसी परिवार को आर्थिक संकट के गर्त में न धकेल दे। सामाजिक सुरक्षा इसी मानवीय विकास का आधार है। यह केवल सरकारी सहायता की व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिकों के सम्मान, आत्मविश्वास, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय का ऐसा आधारस्तंभ है, जिस पर एक सशक्त एवं समावेशी राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में जनकल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को व्यापक बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इन पहलों ने करोड़ों लोगों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक, स्वास्थ्य, खाद्य और सामाजिक सहायता से जोड़ने में भूमिका निभाई है। हालांकि, बदलती आर्थिक परिस्थितियों और विशाल श्रमबल की आवश्यकताओं को देखते हुए अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा वर्ष 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 64.3 प्रतिशत यानी 94 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच गया है। यह विस्तार बताता है कि सामाजिक संरक्षण अब देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा की सफलता का आकलन केवल लाभार्थियों की संख्या से नहीं होना चाहिए। वास्तविक प्रश्न यह है कि कितने

लोगों को आवश्यकता के समय पर्याप्त सहायता मिलती है, कितने परिवार बीमारी और बेरोजगारी के संकट से उबर पाते हैं तथा कितने श्रमिक बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्थिति में हैं। योजनाओं की व्यापकता के साथ उनकी पर्याप्तता, गुणवत्ता और निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सामाजिक सुरक्षा का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहां श्रमबल का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा है। उपलब्ध श्रम संबंधी आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल श्रमबल में लगभग 87 प्रतिशत हिस्सेदारी असंगठित क्षेत्र की है। खेतों में काम करने वाले किसान-मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदार, दैनिक वेतनभोगी और विभिन्न सेवाओं से जुड़े कामगार देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। लेकिन इनमें से बड़ी संख्या के पास नियमित वेतन, भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं हैं। रोजगार मिलने और छिन्ने के बीच उनका जीवन अवसर अनिश्चितता से घिरा रहता है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा को केवल संगठित क्षेत्र तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। इसकी पहुंच उन हाथों तक भी सुनिश्चित करनी होगी, जो देश की उत्पादन व्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था को अपने श्रम से संचालित करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनधन खातों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार आधारित पहचान और डिजिटल सार्वजनिक अवसरचना के माध्यम से सरकारी सहायता को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक व्यवस्था विकसित की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में योगदान दिया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने अनेक योजनाओं में वित्तीयों की भूमिका कम करने और सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इन व्यवस्थाओं ने सामाजिक सुरक्षा

योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी बनाने की संभावनाएं मजबूत की हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा सामाजिक संरक्षण का सबसे संवेदनशील पक्ष है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना के माध्यम से स्वास्थ्य कवरज के दायरे में लाने की पहल ने वृद्धावस्था में चिकित्सा संबंधी चिंताओं को कम करने का प्रयास किया है। फिर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दवाओं तथा जांच की लागत कम करने की आवश्यकता बनी हुई है। गंभीर बीमारी के कारण किसी परिवार की वर्षों की बचत समाप्त हो जाना या उसे कर्ज लेने के लिए विवश होना सामाजिक सुरक्षा की अपूर्णता को उजागर करता है। स्वास्थ्य सुविधाएं तभी प्रभावी सुरक्षा कवच बनेंगी, जब उपचार की उपलब्धता के साथ उसकी वहनियता भी सुनिश्चित होगी।

आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी पहलें अलग-अलग वर्गों की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। पीएम-किसान के माध्यम से पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिलती है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था में नियमित आय की व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करती है। जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजनाएं क्रमशः जीवन बीमा तथा दुर्घटना बीमा के माध्यम से परिवारों को संभावित आर्थिक संकट से बचाने में सहायक हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे पीएम-पोषण के नाम से जाना जाता है,

सत्ता परिवर्तन का रास्ता भीड़तंत्र नहीं, जनमत- लोकतंत्र से

(लेखक- सौरभ वाण्यंय)

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि विविधताओं, सहिष्णुता, शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहचाना जाने वाला देश भी है। यहां सत्ता परिवर्तन का अधिकार जनता को प्राप्त है और यही अधिकार भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब देश में सत्ता परिवर्तन को लेकर बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम का उदाहरण दिया जाता है या रिजौम चेंज अर्थात शासन व्यवस्था को बदलने की बात कही जाती है, तो इस विषय पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे विशाल और परिपक्व लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का रास्ता संवैधानिक व्यवस्था, जनमत और शांतिपूर्ण आंदोलनों से होकर गुजरना चाहिए, न कि भीड़ के दबाव अथवा अराजकता से।

हाल के दिनों में विपक्ष पर भारत में भी बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने के आरोप लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के संदर्भ में भी रिजौम चेंज की बहस सामने आई है। ऐसे बयानों और आरोपों का मूल्यांकन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के बयान का वास्तविक अर्थ उसके पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है। केवल किसी शब्द के आधार पर किसी व्यक्ति या पुरे विपक्ष की मंशा पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। फिर भी, यदि सत्ता परिवर्तन का आशय संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर जाकर सरकार को हटाने या व्यवस्था को अस्थिर करने से है, तो ऐसी सोच स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है।

भारत और बांग्लादेश की राजनीतिक, सामाजिक तथा संवैधानिक परिस्थितियों में अंतर है। भारत में नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायालिका, निर्वाचन आयोग, संसद, राज्य विधानसभाएं और संवैधानिक संस्थाएं सत्ता परिवर्तन के स्थापित माध्यम हैं। इन संस्थाओं की मजबूती ही लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करती है। किसी दूसरे देश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को भारत में दोहराने की कल्पना करना न तो आवश्यक है और न ही भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप।

भारत की पहचान शांति, सहिष्णुता और संवाद की परंपरा से रही है। यहां सत्ता किसी व्यक्ति, दल या संगठन की स्थायी संपत्ति नहीं है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन देश और उसकी संवैधानिक व्यवस्था सर्वोपरि रहती

है। इसलिए किसी भी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करना, जिनसे सामाजिक तनाव, हिंसा या संस्थागत अस्थिरता बढ़े, देशहित में नहीं हो सकता।

लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच स्पष्ट अंतर है। लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जाती है, असहमति का सम्मान होता है और निर्णय कानून तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाते हैं। इसके विपरीत, भीड़तंत्र में संख्या और दबाव के बल पर निर्णय थोपने की प्रवृति पैदा हो सकती है। यदि किसी सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर भीड़ जुटाकर संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने या कानून-व्यवस्था को बांधित करने का रास्ता अपनाया जाए, तो यह लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर सकता है। हालांकि, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जनता को आंदोलन करने या सरकार का विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध, धरना, प्रदर्शन, जनसभाएं और जनजागरण लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। जब जनता किसी नीति, निर्णय या शासन के तरीके से असंतुष्ट होती है, तो उसे अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। आवश्यक यह है कि आंदोलन शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहे।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। यदि जनता किसी सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास चुनाव में अपना मत देकर सरकार बदलने का अधिकार है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रभावी और वैध माध्यम है। किसी सरकार की लोकप्रियता का आकलन नारों, सोशल मीडिया अभियानों या भीड़ के आकार से नहीं, बल्कि व्यापक जनमत और चुनावी प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। यदि किसी सरकार की नीतियां जनविरोधी हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती या शासन में गंभीर कमियां दिखाई देती हैं, तो विपक्ष का दायित्व है कि वह इन मुद्दों को जनता के सामने रखे। उसे वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करनी चाहिए, सरकार से जवाब मांगना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से जनसमर्थन हासिल करना चाहिए। यदि जनता विपक्ष के विचारों से सहमत होती है, तो वह चुनाव में उसे सत्ता सौंप सकती है। इसमें न कोई असामान्यता है और न ही किसी प्रकार की अस्थिरता; यही लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है।

इसी प्रकार, यदि जनता वर्तमान सरकार को दोबारा चुनती है, तो उस जनादेश का सम्मान करना भी सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

दान और परोपकार से घटता नहीं है धन

सभी धर्मों में कहा गया है कि दान करो। दान करने से धन घटता नहीं है बल्कि आपका धन बढ़ता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग धन बढ़ने का तात्पर्य यह समझते हैं कि आज आप सौ रुपये कमाते हैं तो कल हजार रुपये कमाने लगेंगे। शायदों में मुद्रा को धन कभी कहा ही नहीं गया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जो पुण्य अर्जित करता है वही धन है। पुण्य रूपी धन परोपकार और जनहित से बढ़ता है। मुद्रा रूपी धन तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको कीस्मत में होगा। अगर आप दान भी कर दें तो आपके पास उतना ही रहेगा जितना आपके भाग्य में है। अगर आप संचित करके भी रखेंगे तब भी उतना ही बचेगा जितना आपको कीस्मत में विधाता ने लिख दिया है।

दक्षिण भारत की एक कथा है इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। एक गरीब ब्राह्मण था। दिन भर अपना काम करता इसके बाद जो भी समय बचता उसे भगवान की सेवा में लगा देता। ब्राह्मण की पुत्नी अक्सर ब्राह्मण से कहती पूजा-पाठ से क्या लाभ है भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, पता नहीं हमारी गरीबी कब दूर होगी। एक दिन ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्रह्मण बहुत दुःखी

फंसती चली जा रही है। न्यायपालिका के ऊपर भी भारी दबाव है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी खुलकर न्यायपालिका में जजों और सरकार के खिलाफ पर्याप्त दबाव बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि सरकार विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन कानून को पास कराने की जिद में अड़ती है तो कहा जा सकता है कि सरकार एक बड़ा रिस्क ले रही है। जब सरकार के खिलाफ एक तूफान देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति में उस भ्रवर में फंसने के स्थान पर सरकार को अपने आप को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इस तरह का जोखिम उठाना एक बड़ा दुस्साहस है। सरकार को दो तिहाई बहुमत जुटाने के लिए 360 सांसदों के मत की जरूरत होगी। अभी एनडीए के पास 318

सांसद हैं। डीएमके के यदि 22 सांसद बिल का समर्थन करते हैं तो यह संख्या बढ़कर 340 हो जाएगी। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 20 सांसदों की जरूरत है। राज्यसभा में एनडीए के पास 153 सांसद हैं, राज्यसभा में 162 सांसदों की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर इतने नेरो मार्जिन के साथ सरकार इतना बड़ा जोखिम ले रही है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है सरकार को अपने आप को बचाए रखने के लिए या तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसे यह जोखिम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। बहरहाल जो भी सरकार विशेष सत्र बुलाकर यदि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को पास करने की जिद में अड़ी हुई है तो यह उसके लिए एक

उपलब्ध रहने वाली सुविधाएं तथा निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं तक सरल पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा का ऐसा लचीला मॉडल विकसित होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति के नियोत्ता, कार्यस्थल अथवा निवास स्थान बदलने पर भी उसके अधिकार बाधित न हों।

इसके साथ ही वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की राशि को महंगाई के अनुरूप अधिक पर्याप्त बनाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने और असंगठित श्रमिकों के लिए योगदान आधारित पेंशन तथा बीमा विकल्पों को सरल एवं सुलभ बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। पंचायतों, नगर निकायों और साझा सेवा केंद्रों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रसार तथा पंजीकरण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विकसित भारत का स्वन तभी साकार होगा, जब आर्थिक विकास के साथ सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा भी समान गति से आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा का विस्तृत होता दायरा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन को रेखांकित करता है। लेकिन अगला चरण केवल योजनाओं के विस्तार का नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और अंतिम व्यक्ति तक वास्तविक लाभ पहुंचाने का होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पर होने वाला व्यय सरकारी खजाने पर बोझ नहीं, बल्कि स्वस्थ, उत्पादक और आत्मविश्वासी समाज के निर्माण में निवेश है। जब श्रमिकों को भविष्य की चिंता से राहत मिलेगी, किसान को संकट में सहारा मिलेगा, वृद्ध को सम्मानपूर्ण जीवन और गरीब परिवार को बीमारी के समय उपचार का भरोसा मिलेगा, तभी विकास की उपलब्धियां जनजीवन में सार्थक परिवर्तन ला सकेंगी। यही समावेशी विकास की वास्तविक कसौटी और एक सशक्त, संवेदनशील तथा आत्मनिर्भर भारत की आधारभूमि है।

(यह लेखक के व्य किंगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

ट्रंप की मजबूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमनो फैसले लेने और उन पर टिके न रहने की आदत किस तरह कायम है, इसका नया उदाहरण है उनकी यह घोषणा कि अब वे रूस से तेल खरीदने वाले भारत समेत पांच देशों पर सौ प्रतिशत टैरिफ वाले कानून पर अमल नहीं करेंगे। निःसंदेह यह घोषणा भारत को राहत देने वाली है, लेकिन इसी के साथ वह ट्रंप के अस्थिर स्वभाव के साथ उनकी मजबूरी को भी रेखांकित करने वाली है।

उनका सौ प्रतिशत टैरिफ वाला कानून मनमाना ही नहीं, वैश्विक ऊर्जा हितों को नुकसान पहुंचाने वाला भी था। वे इस कानून को लागू करने से इसलिए पीछे हटने को बाध्य हुए कि अमेरिका ने खुद रूस से तेल खरीदने का निर्णय ले लिया। इसके बाद यदि वे इस कानून पर अमल करते तो जगहसाईं के पात्र बनते और उनके दोहरे मानदंडों की पोल खुलती। यही नहीं, यदि वे इस कानून को लागू कर देते तो भारत से व्यापार समझौते की संभावना न्यून कर लेते, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि वह अमेरिकी मनमानी सहन करने को तैयार नहीं। ट्रंप के ऐसे फैसलों की एक लंबी सूची है, जिनसे वे पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। अपने ऐसे फैसलों से वे

अमेरिका के साथ अपनी भी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं रह गया है। वे ऐसे फैसलों के लिए भी कुख्यात हो रहे हैं, जिनके तात्कालिक असर से या तो उनके स्वजन या फिर उनके करीबियों के आर्थिक हित पूरे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उनके कई फैसले दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर डालते हैं। इसका लाभ ट्रंप स्वयं अथवा उनके करीबी उठाते हैं। ट्रंप मूलतः एक कारोबारी हैं और यह केवल विश्व समुदाय की धारणा नहीं कि वे निजी वित्तीय हितों के लिए अपने पद का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी नागरिक भी यह मान रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका से ज्यादा खुद के वित्तीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इनमें उनकी पार्टी रिपब्लिकन के भी समर्थक हैं। तथ्य यह भी है कि उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने पर अपने परिवार के कारोबारी सौदों पर लगी पाबंदियां हटाईं और बेटे के स्वामित्व वाली कंपनी के जरिये क्रिंटो कारोबार शुरू किया। इस क्रिंटो कारोबार के साथ उनके रियल एस्टेट व्यवसाय में दूसरे देशों के बड़े उद्यमी भागीदार बने हैं। ट्रंप परिवार या उनके करीबियों की कंपनियों के कुछ सौदों में तो दूसरे देशों की सरकारें भी इस लाभ में भागीदार बनीं कि ट्रंप उनके प्रति उदार रहेंगे। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान है, जिसने आनन-फानन क्रिंटो कारोबार वाली संस्था खड़ी कर ट्रंप परिवार की कंपनी से हाथ मिलाया। बदले में ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करने में जुट गए।

संसद का विशेष सत्र सरकार के लिए आग का दरिया?

(लेखक- सनत जैन)
पिछले कुछ दिनों से लगातार खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। दरअसल अभी तक मानसून सत्र का अवसान नहीं हुआ है। इसके पहले 16 से 18 अप्रैल 2026 को 30 दिन का विशेष सत्र पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले बुलाया गया था। परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन कानून के रूप में इसे पेश किया गया था 131 वां संविधान संशोधन विधेयक जिसे दो तिहाई बहुमत से पास होना था यह उस समय संसद में पास नहीं हो पाया था। इस बिल को दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पास होना जरूरी था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। पूरे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की स्थिति

को लेकर धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना में बगावत हो गई है। बिहार में जिस तरह से जनता दल यू

को तोड़ा गया है, इस समय क्षेत्रीय दलों में

जिस तरह भय भाजपा को लेकर देखा जा रहा है, आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर

तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं।

जनमत इस समय सरकार के खिलाफ जाता

हुआ दिख रहा है। सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। सहयोगी दलों के सहारे

सरकार बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इसे

सरकार के लिए एक बड़ा खतरा भी माना जा

रहा है। देश में 50 साल के बाद एक बार फिर

जनता सड़कों पर आ गई है 13 करोड़ से

ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे गए थे। अब

एक-एक करके सरकार नई-नई मुसीबतों में

गई है, जिसके कारण दल-बदल कानून के

अंतर्गत सांसदों की सदस्यता भी खतरे में पड़ी

हो गई है। बिहार में जिस तरह से जनता दल यू

को तोड़ा गया है, इस समय क्षेत्रीय दलों में

जिस तरह भय भाजपा को लेकर देखा जा रहा

है, आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर

तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं।

जनमत इस समय सरकार के खिलाफ जाता

हुआ दिख रहा है। सरकार के पास स्पष्ट बहुमत

नहीं है। सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनी

हुई है। ऐसी स्थिति में इसे सरकार के लिए एक

बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। देश में 50 साल

के बाद एक बार फिर जनता सड़कों पर आ गई

है 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे गए

थे। अब एक-एक करके सरकार नई-नई मुसीबतों

में गई है, जिसके कारण दल-बदल कानून के अंतर्गत

सांसदों की सदस्यता भी खतरे में पड़ी हो गई है।

बिहार में जिस तरह से जनता दल यू को तोड़ा

गया है, इस समय क्षेत्रीय दलों में जिस तरह भय

भाजपा को लेकर देखा जा रहा है, आंध्र प्रदेश में

भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं

सामने आ रही हैं। जनमत इस समय सरकार के

खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। सरकार के पास

स्पष्ट बहुमत नहीं है। सहयोगी दलों के सहारे सर

कारक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इसे सरकार के

लिए एक बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। देश में

50 साल के बाद एक बार फिर जनता सड़कों पर आ

गई है 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे

गए थे। अब एक-एक करके सरकार नई-नई मुसीबतों

में गई है, जिसके कारण दल-बदल कानून के अंतर्गत

सांसदों की सदस्यता भी खतरे में पड़ी हो गई है।

बिहार में जिस तरह से जनता दल यू को तोड़ा

गया है, इस समय क्षेत्रीय दलों में जिस तरह भय

भाजपा को लेकर देखा जा रहा है, आंध्र प्रदेश में

भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं

सामने आ रही हैं। जनमत इस समय सरकार के

खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। सरकार के पास

स्पष्ट बहुमत नहीं है। सहयोगी दलों के सहारे सर

कारक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इसे सरकार के

लिए एक बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। देश में

50 साल के बाद एक बार फिर जनता सड़कों पर आ

गई है 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे

गए थे। अब एक-एक करके सरकार नई-नई मुसीबतों

में गई है, जिसके कारण दल-बदल कानून के अंतर्गत

सांसदों की सदस्यता भी खतरे में पड़ी हो गई है।

बिहार में जिस तरह से जनता दल यू को तोड़ा

गया है, इस समय क्षेत्रीय दलों में जिस तरह भय

भाजपा को लेकर देखा जा रहा है, आंध्र प्रदेश में

भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं

सामने आ रही हैं। जनमत इस समय सरकार के

खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। सरकार के पास

स्पष्ट बहुमत नहीं है। सहयोगी दलों के सहारे सर

कारक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इसे सरकार के

लिए एक बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। देश में

50 साल के बाद एक बार फिर जनता सड़कों पर आ

गई है 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे

गए थे। अब एक-एक करके सरकार नई-नई मुसीबतों

में गई है, जिसके कारण दल-बदल कानून के अंतर्गत

सांसदों की सदस्यता भी खतरे में पड़ी हो गई है।

बिहार में जिस तरह से जनता दल यू को तोड़ा

गया है, इस समय क्षेत्रीय दलों में जिस तरह भय

भाजपा को लेकर देखा जा रहा है, आंध्र प्रदेश में

भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं

सामने आ रही हैं। जनमत इस समय सरकार के

खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। सरकार के पास

स्पष्ट बहुमत नहीं है। सहयोगी दलों के सहारे सर

कारक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इसे सरकार के

लिए एक बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। देश में

50 साल के बाद एक बार फिर जनता सड़कों पर आ

गई है 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे

गए थे। अब एक-एक करके सरकार नई-नई मुसीबतों

में गई है, जिसके कारण दल-बदल कानून के अंतर्गत

सांसदों की सदस्यता भी खतरे में पड़ी हो गई है।

बिहार में जिस तरह से जनता दल यू को तोड़ा

अवतार के रूप में क्यों आते हैं भगवान

भगवान के अवतार के तीन कारण होते हैं- पहला अनुग्रह अथवा साधुपरित्राण, दूसरा निग्रह अथवा दुष्कृतकारियों का विनाश और तीसरा धर्मसंस्थापन। जिस प्रकार कोई सम्राट अपने साम्राज्य में सज्जनों को पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित करके और दुर्जनों को तिरस्कार द्वारा निरुत्साहित करके प्रजा में अभ्युदयशील सामंजस्य स्थापित करता है, उसी प्रकार श्रीभगवान भी यथासमय अवतीर्ण होकर यथायोग्य निग्रहानुग्रह प्रदर्शित करते हुए अपनी सृष्टि में धर्म की स्थापना किया करते हैं। समस्त धर्मों का पर्यवसान श्रीभगवत साक्षात्कार में ही है। भगवत साक्षात्कार तभी हो सकता है, जब भगवान में निष्ठा हो। निष्ठा तभी होती है जब अनुराग हो, अनुराग उसी में होता है, जिसकी ओर आकर्षण होगा। अतएव जीवजात को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही भगवान अवतार रूप में ऐसी-ऐसी मनमोहिनी क्रीड़ाएं करते हैं कि जिन्हें सुनकर श्रोताओं का मन उनमें बलात् आसक्त हो जाता है।

बालक, युवक और वृद्ध, पंडित और मूर्ख, राजा और प्रजा, स्त्री और पुरुष, विषयी और विरागी, सभी का भगवल्लीला श्रवण से उधर आकर्षण होता है, जो परिणाम में प्रपंचातीत परमात्मा तक पहुंचा देता है। ज्ञान-विज्ञान विनाशन काम को गीता में आचार्य रामानुज के अनुसार बुद्धि से भी बलवत्तर बताया गया है। उसी महापाप, महावेरी, दुष्पूर काम को भक्तजन अनायास जीत सकें, इसलिए भगवान अपने अवतार चरित्रों द्वारा मदन-दमन लीलाएं करते हैं। उदाहरण के लिए कोटि-कन्दर्पदर्पा श्रीकृष्ण की योगमाया द्वारा प्रसाधित रासलीला का दर्शन करके उस समय अनेक देवादि भी भगवन्निष्ठ होकर कृतकृत्य हो गये और अब भी उस परम उज्ज्वल लीला का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करने वालों के मदनरूपी हृदय रोग का स्वयमेव शमन हो जाता है।

नित्यविभूति से लीलाविभूति में श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि रूपों में श्रीभगवान का अवतार आगम ग्रंथों में विभक्त कहलाता है। श्रीमत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम (जामदग्न्य), राम (दाशरथि), कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये दस अवतार प्रसिद्ध हैं। श्रीवराह, सनकादि, नारद, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि- ये 22 अवतार कहलाते हैं। हंस और हयग्रीव की संख्या मिलाने से यह 24 होते हैं। आगम ग्रंथों में अन्यान्य अवतारों के भी नाम उपलब्ध होते हैं।

विभव के दो भेद हैं- स्वरूपावतार और आवेशावतार। जब श्रीभगवान स्वरूप में अर्थात् स्वयं ही अवतीर्ण होते हैं, तब उनका वह रूप स्वरूपावतार कहलाता है, जैसे दाशरथि श्रीराम, किंतु जब किसी जीव विशेष में परमात्मा की शक्ति का आवेश होता है, तब उसे आवेशावतार कहते हैं, जैसे जामदग्न्य राम। जिस रूप में परब्रह्म परमात्मा अपने समग्र ऐश्वर्य माधुर्य को लिये हुए ही अवतीर्ण होते हैं, उसे पूर्णावतार कहते हैं। किंतु जिस रूप में आवश्यकतानुसार वे अपने प्रभाव का आंशिक प्राकट्य ही दिखलाते हैं, उसको अंशावतार कहते हैं। अंश के तुरीय भाग को कला कहते हैं। अतएव अंशावतार का अवान्तर भेद होने से कलावतार को उसी के अन्तर्भूत समझना चाहिए।



बृहस्पति जी को देवगुरु पद किसने प्रदान किया

पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अगिरा ऋषि का विवाह स्मृति से हुआ। जिनसे सिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति नाम कि कन्याएं एवं उतथ्य व जीव नामक पुत्र हुए। जीव बचपन से ही शांत एवम जितेन्द्रिय प्रकृति के थे। वे समस्त शास्त्रों तथा नीति के ज्ञाता हुए। अगिरा नंदन जीव ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग कि स्थापना कि तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया।

महादेव ने उनकी आराधना एवं तपस्या से प्रसन्न हो कर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ ! तुमने बहुत तप किया है। अतः तुम बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध हो कर देवताओं के गुरु बनो और उनका धर्म व नीति के अनुसार मार्गदर्शन करो। इस प्रकार महादेव ने बृहस्पति को देवगुरु पद और नवग्रह मंडल में स्थान प्रदान किया। तभी से जीव, बृहस्पति और गुरु के नाम से विख्यात हुए। देवगुरु कि शुभा,तारा और ममता तीन पत्नियां हैं। उनकी तीसरी पत्नी ममता से भरद्वाज एवं कच नामक दो पुत्र हुए। बृहस्पति ग्रह सब ग्रहों में सबसे अधिक वजनी और पृथ्वी से बहुत नजदीक 37 करोड़ मील से भी कम दूरी पर हैं। इस ग्रह पर वायु नहीं है इसके धरातल पर हमेशा लामा फूटता रहता है इसलिए जो हमारे गुरुजन है उनके अन्दर जो ज्ञान रूपी लावा है वो हमारे कल्याण के लिए निरंतर बहता रहता है।

गणेश मंत्र करेगा सभी कामनाओं की पूर्ति

गणपति जी का बीज मंत्र गं है। इनसे युक्त मंत्र- ऊँ गं गणपतये नमः का जप करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।

- बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो श्री गणेश जी के मंत्र ऊँ गं गणपतये नमः का एक माला जप करें और 11 मोदक या लड्डू का भोग लगाएं।
- बच्चे का मन पढ़ाई में न लग रहा हो तो प्रत्येक बुधवार ऊँ गं गणपतये नमः

जिस प्रकार कोई सम्राट अपने साम्राज्य में सज्जनों को पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित करके और दुर्जनों को तिरस्कार द्वारा निरुत्साहित करके प्रजा में अभ्युदयशील सामंजस्य स्थापित करता है, उसी प्रकार श्रीभगवान भी यथासमय अवतीर्ण होकर यथायोग्य निग्रहानुग्रह प्रदर्शित करते हुए अपनी सृष्टि में धर्म की स्थापना किया करते हैं। समस्त धर्मों का पर्यवसान श्रीभगवत साक्षात्कार में ही है।



सरल उपाय अपनाएं

शर्तियां वास्तुदोष भगाएं

- घर का मुख्य द्वार सदैव पूर्व या उत्तर में ही होना चाहिए किंतु यदि ऐसा न हो पा रहा हो तो घर के मुख्य द्वार पर 'स्वास्तिक' की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। घर की स्थिति अनुकूल होने लगती है।
- घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखें। सुबह उसमें जल अर्पित करें तथा शाम को दीपक जलाएं। पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है। घर की छत पर तुलसी का पौधा रखने से घर पर बिजली गिरने का भय नहीं रहता। घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर में पांच तुलसी के पौधे लगाएं तथा उनकी नियमित सेवा करें।
- ध्यान रहे कि घर में खिड़की दरवाजों की संख्या सम हो जैसे (2, 4, 6, 8, 10) तथा दरवाजे खिड़कियां अंदर की तरफ ही खुलें। द्वार खोलते-बंद होते समय किसी भी प्रकार की कर्कश ध्वनि नहीं आनी चाहिए। ये अशुभ सूचक होता है।
- यदि किसी भिक्षुक को भिक्षा देनी हो तो घर से बाहर आकर ही दें अन्यथा अनहोनी होने की संभावना रहती है।
- इस बात का ध्यान रहे कि घर में कभी भी फालतू सामान, टूटे-फूटे फर्नीचर, कूड़ा कबाड़ तथा बिजली का सामान इकट्ठा न होने पाए। अन्यथा घर में बेवजह



का तनाव बना रहेगा।

- घर के किसी भी कोने में सीलन नहीं होनी चाहिए और न ही घर के किसी कोने में रात को अंधेरा रहना चाहिए। शाम को कम से कम 15 मिनट पूरे घर की लाइट अवश्य जलानी चाहिए। बिजली के स्विच, मोटर, मेन मीटर, टी.वी., कम्प्यूटर आदि आग्नेय कोण में ही होने चाहिए इससे आर्थिक लाभ सुगमता से होता है।
- घर में पुस्तकें रखने का स्थान उत्तर या पूर्व में ही होना चाहिए तथा पुस्तकों को बंद अलमारी में ही रखना चाहिए।
- घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं लगने चाहिए नहीं तो राहु खराब होता है तथा राहु के बुरे फल भोगने पड़ते हैं।
- संध्या के समय घर में एक दीपक अवश्य जलाएं तथा ईश्वर से अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा याचना करें।

शनि देव लंगड़े एवं शनेश्वर क्यों कहलाते हैं?

सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनका तेज सहन न कर पाने से अपनी प्रतिमूर्ति छाया को प्रकट कर और उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप तपस्या करने चली गई। छाया संज्ञा का प्रतिरूप बन सूर्यदेव के साथ सुखी दांपत्य जीवन व्यतित करने लगी। इस दौरान छाया और सूर्यदेव के पांच पुत्र हुए। जब उसके स्वयं के बच्चे हो गए तो उसका मन उनमें ही रम गया और संज्ञा के बच्चों के प्रति उसका विमाता सा व्यवहार हो गया। एक दिन छाया अपने बच्चों को खाना परोस रही थी। शनिदेव भूख से व्याकुल होकर छाया के पास आए और उनसे भोजन परोसने को कहने लगे पर छाया ने उनकी तरफ ध्यान न दिया। अपने बच्चों को प्रेमपूर्वक भोजन कराती रही। छाया के व्यवहार से शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने छाया को मारने के लिए अपनी टांग उठायी। तभी छाया ने शनिदेव को श्राप देते हुए कहा कि, तेरी यह टांग अभी टूट जाए। उसी समय शनिदेव लंगड़े हो गए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव को कू ग्रह माना जाता है। मान्यता है की जिसकी कुण्डली में शनि नकारात्मक भाव में हो उसे बहुत सी मुसिबतों का सामना करना पड़ता है। वह नौ ग्रहों में सबसे धीमे ग्रह हैं क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से शनि लंगड़ा है और एक राशि में करीब द्वाई वर्ष तक रुकता है। इसी वजह से इन्हें शनेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये शैः शैः चलते हैं।

मंत्र के साथ 11 दूर्वा 6 हरी घास 8 गणेश जी को अर्पित करें।

- व्यवसाय न चल रहा हो या घाटे पड़ रहे हो तो प्रत्येक बुधवार 11 दूर्वा ऊँ गं गणपतये नमः मंत्र के साथ चढ़ावे तथा 21 लड्डू का भोग लगा कर ग्राहकों में बांटे।
- चूहों से परेशान हैं तो एक कटोरी में जल लेकर ऊँ गं गणपतये नमः मंत्र को पढ़कर कटोरी को रात भर जमीन पर रख दें सुबह जल पौधों में डाल दें। चूहे भाग जाएंगे।
- अगर आपका व्यवसाय बन्द होने के कगार पर है तो 108 लड्डू 108 दूर्वा के साथ गणेश जी का अभिषेक कराएं।

इस मंत्र जाप के अतिरिक्त गणपति अथर्वशीर्ष, संकटनाशक गणेश स्त्रोत, गणेशकवच, संतान गणपति स्त्रोत, ऋहर्ता गणपति स्त्रोत, मयूरेश स्त्रोत, गणेश चालीसा का पाठ करने से गणेश जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है।



संक्षिप्त

समाचार

यमन के अदन एयरपोर्ट पर फिर हमला; उड़ान भरने को तैयार विमान के पास गिरी मिसाइलें

साना, एजेंसी। यमन के बंदरगाह शहर अदन के हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात दो मिसाइलें गिरने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। मिसाइलें यमनिया एयरवेज के एक विमान से करीब 500 मीटर दूर गिरीं। उस समय विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। हमले से घबराए यात्रियों में चीख-पुकार मचने के बाद उनको तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यमन के रणनीतिक बंदरगाह शहर अदन के हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात दो मिसाइलें गिरीं। पुलिस के अनुसार, यह पिछले 10 दिनों से भी कम समय में हवाई अड्डे पर दूसरा मिसाइल हमला है। इससे पहले 7 अक्टूबर को भी यहां दो मिसाइलें दागी गई थीं। उस घटना में भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी। इस बार हमले के दौरान यमनिया एयरवेज का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। यमन सरकार के सूचना मंत्री के अनुसार, मिसाइलें विमान से लगभग 500 मीटर दूर गिरीं। एक अधिकारी ने बताया कि विमान में सवार यात्रियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

अमेरिका में गैर-कानूनी रूप से मतदान करने के आरोपी में भारतीय नागरिक गिरफ्तार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के मिनेसोटा में 2024 के आम चुनाव में अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा करके वोट करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान मुकेशकुमार सोमाभाई चौधरी के रूप में की गई है. अमेरिकी जांच अधिकारियों ने चौधरी पर वोटिंग में जानबूझकर गलत जानकारी देने और वोट देने के लिए रजिस्टर करने या वोट देने के लिए नागरिकता का झूठा दावा करने का आरोप लगाया है. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक, अगर चौधरी को दोषी पाया जाता है, तो उसे हर मामले में ज्यादा पांच साल जेल की सजा हो सकती है. चार्जशीट के मुताबिक, चौधरी ने 5 नवंबर, 2024 को एक वोटर सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर साइन किया था, जैसा कि मिनेसोटा कानून के तहत आम चुनाव में वोट देने के लिए जरूरी है. दस्तावेज में उसे यह शपथ लेने या पुष्टि करने की जरूरत थी कि वह एक अमेरिकी नागरिक है. जांच अधिकारियों का आरोप है कि वह नागरिक नहीं था और उसने जानबूझकर वोट देने के लिए झूठी घोषणा की. होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल एजेंट दैविश पिकार्ड ने कहा, ‘सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही मतदान कर सकते हैं, और वोट डालने के लिए नागरिकता का झूठा दावा करना एक गंभीर अपराध है. हम अपनी चुनाव प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए अपने कानून लागू करने वाले दूसरे अधिकारियों के साथ काम करना जारी रखेंगे.’ ‘डा।एस.सिवा मार्कवेन मुलिन ने कहा, ‘अमेरिकी चुनावों में मतदान करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए हमारा संदेश स्पष्ट है: हम आपको ढूढ़ लेगे, आपको गिरफ्तार करेंगे और आपको आपराधिक मामलों और निर्वासन सहित परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

किम जोंग का शक्ति प्रदर्शन: उत्तर कोरिया ने एआई-बेस्ड टॉरपीडो सिस्टम का किया परीक्षण

सियोल, एजेंसी। उत्तर कोरिया ने शनिवार को कहा कि उसने एक नए टॉरपीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो लक्ष्य का पता लगाने और दिशा-निर्देशन (गाइडेंस) के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करता है। कोरियन सेंद्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने बताया कि गुरुवार को जिस हथियार का परीक्षण किया गया, वह ‘जैम-2.0’ नाम का एक बेहद तेज गति वाला और सटीक गाइडेड टॉरपीडो सिस्टम है। हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनका क्या तात्पर्य है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस परीक्षण से हथियार के प्रोपल्शन सिस्टम (आगे बढ़ाने वाली प्रणाली) की पुष्टि हुई है, जिसे पिछले पांच वर्षों में 180 से अधिक परीक्षणों के जरिए विकसित किया गया था। दक्षिण कोरिया की सेना, जो अक्सर उत्तर कोरिया पर अपनी सैन्य तकनीकों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का आरोप लगाती है, ने केसीएनए की इस रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कि हाल के हप्तों में उत्तर कोरिया ने हथियारों के प्रदर्शन को तेज कर दिया है।

लाओस में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी से वियतनाम की चिंता बढ़ी, क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंडराया खतरा

विंएितियाने, एजेंसी। लाओस में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। खास तौर पर वियतनाम के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह लंबे समय से लाओस को अपनी पश्चिमी सीमा पर रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से अहम सहयोगी मानता रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों, लाओस में नेतृत्व परिवर्तन और बीजिंग पर बढ़ती आर्थिक निर्भरता के बीच हनौई के सामने अपने पारंपरिक प्रभाव को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो रही है। लोबी इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ हेंटर मार्स्टन ने पिछले सप्ताह कहा था कि वियतनाम को पहले से ही चारों ओर से घिरने की आशंका है, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों और सैन्य ठिकानों को लगातार मजबूत कर रहा है।

चीन के सैन्य केंद्र के बाद वियतनाम-लाओस की अहम बैठक : 8 अक्टूबर को वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग ने लाओस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री सलेमक्से कोम्मासिथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विशेष संबंधों को दोहराया। हालांकि, इस बैठक का महत्व इसके समय को लेकर अधिक है। यह मुलाकात चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से लाओस के बान केउन हवाई अड्डे पर संयुक्त सैन्य सहायता और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा के करीब एक सप्ताह बाद



हुई। इसके अलावा, यह लाओस की नेशनल असेंबली द्वारा सलेमक्से को प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ ही दिनों बाद आयोजित की गई। उन्होंने सोनेक्से सिफानडोन की जगह ली है, जिन्हें अब नेशनल असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया है।

बीजिंग का कहना है कि इस केंद्र का उद्देश्य लाओस की वायु सेना के पायलटों को प्रशिक्षण देना है और इसका इस्तेमाल किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक, केंद्र की वास्तविक भूमिका का आकलन उसके आधिकारिक नाम से नहीं, बल्कि वहां तैनात सैन्यकर्मियों, उपकरणों और भविष्य में उसकी गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा। उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों में वहां हल्के लड़ाकु विमान और सहायक वाहन दिखाई देने की बात सामने आई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय

में केंद्र का विस्तार किस हद तक होता है और वहां सैन्य पहुंच तथा तैनाती से जुड़े नियम क्या रहते हैं।

लाओस में नेतृत्व परिवर्तन से हनौई की चिंता : लाओस में सत्ता परिवर्तन भी वियतनाम के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानडोन के परिवार के वियतनाम के साथ लंबे समय से करीबी संबंध रहे हैं। उनके पिता और लाओस के पूर्व राष्ट्रपति खामते सिफानडोन को वियतनामी नेतृत्व एक पुराने मित्र के रूप में देखा था। अप्रैल 2025 में खामते के निधन के बाद लाओस ने पांच दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी, जबकि वियतनाम में दो दिन का शोक मनाया गया था। यह दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है।

हालांकि, सोनेक्से का प्रधानमंत्री पद छोड़ना अपने आप में यह संकेत नहीं है कि लाओस की राजनीति में

वियतनाम का प्रभाव समाप्त हो रहा है। उन्हें नेशनल असेंबली का अध्यक्ष बनाया जाना बताता है कि वह अब भी देश की सत्ता व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसी तरह, नए प्रधानमंत्री सलेमक्से कोम्मासिथ की नियुक्ति को भी सीधे चीन समर्थक गुट की जीत के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। उनके राजनयिक करियर में रूस और ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्राप्त करना तथा पश्चिमी देशों के साथ संबंधों से जुड़े दायित्व निभाना शामिल रहा है।

आर्थिक जरूरतें बदल रही हैं लाओस की रणनीति : विश्लेषण के मुताबिक, लाओस की विदेश नीति में बदलाव को समझने के लिए उसकी आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान देना जरूरी है। देश को निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक स्थिरता की जरूरत है। ऐसे में उसकी सरकार उन देशों के साथ समझौते करने के लिए तैयार हो सकती है, जो इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।

वियतनाम के लिए चिंता की बात यह है कि लाओस की नीतियों में पारंपरिक राजनीतिक और वैचारिक निकटता के मुकाबले आर्थिक लाभ को अधिक महत्व दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लाओस चीन के प्रति पूरी तरह राजनीतिक रूप से झुक गया है। बल्कि, आर्थिक दबाव और विकास की जरूरतें उसके रणनीतिक विकल्पों को प्रभावित कर सकती हैं।

इंडोनेशिया : बाली में पेट्रोल-डीजल खत्म!, पंपों पर लगे ‘क्षमा करें, ईंधन उपलब्ध नहीं है’ के बोर्ड



स्थानीय स्तर पर वितरण (डिस्ट्रिब्यूशन) की समस्याओं की वजह से हुई है। ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय में तेल और गैस विभाग के महानिदेशक, लाओडे सुलेमान ने कहा, ‘यह पूरी तरह से वितरण से जुड़ी समस्या है। एक ईंधन टैंकर अभी में देरी हो गई थी, लेकिन अब वह पहुंच चुका है और 24 घंटे ईंधन की सप्लाई जारी है।’ सुलेमान ने बताया कि बाली आ रहे एक ईंधन टैंकर में अनलोडिंग (ईंधन उतारने) की तैयारी के दौरान

तकनीकी खराबी आ गई, जिससे द्वीप के मुख्य ईंधन टर्मिनलों तक सप्लाई पहुंचने में देरी हुई। इसके अलावा, समुद्र में तेज लहरों और खराब मौसम के कारण डेनपासार के सांगरान टर्मिनल और पूर्वी बाली के मांगिण टर्मिनल तक भी ईंधन की खेप पहुंचने में देरी हुई। इंडोनेशिया के तेल और गैस महानिदेशक के अनुसार अब ईंधन की आपूर्ति के लिए होने वाली निविदाओं (टेंडस) में बहुत कम लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस वजह से

सरकार को उन देशों से सीधे ईंधन मांगना पड़ रहा है, जिनके पास अतिरिक्त स्टॉक है, और इसके लिए उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद, इंडोनेशिया के ईंधन आयात के 25% स्रोत खत्म हो गए। समस्या तब बढ़ी जब सरकारी सब्सिडी वाले ‘पटोलाइट’ पेट्रोल की भारी मांग देखी गई, जो बिना सब्सिडी वाले ईंधन की तुलना में काफी सस्ता है। ईंधन की कमी की आशंका से घबराए वाहन चालकों ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। पत्र में प्रामिला जयपाल ने भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुरोरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मसौदा मतदाता सूची से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताई और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

अमेरिका में एच-1बी कर्मचारियों को झटका: वर्क परमिट की 540 दिन की राहत खत्म



वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी सरकार ने कई श्रेणियों के प्रवासियों के वर्क परमिट की 540 दिन की ऑटोमैटिक एक्सपैरेशन सुविधा खत्म कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से हजारों विदेशी कर्मचारियों, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, को काम छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा उन मामलों में हो सकता है, जिनमें वर्क परमिट के नवीनीकरण का आवेदन लंबित है और मौजूदा परमिट की अवधि समाप्त हो जाती है। अमेरिकी नागरिकता एवं आब्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने बुधवार को इस बदलाव को औपचारिक रूप दिया। अंतिम नियम के तहत उस नीति को पक्का किया गया है, जिसे पहली बार पिछले साल 30 अक्टूबर को अंतिम नियम के जरिये लागू किया गया था।

क्या है 540 दिन की एक्सपैरेशन सुविधा : 540 दिन तक वर्क परमिट की ऑटोमैटिक एक्सपैरेशन सुविधा मई 2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इसका मकसद परमिट के नवीनीकरण से जुड़े लंबित मामलों को कम करना और सरकारी प्रक्रिया में देरी के कारण कर्मचारियों को काम करने का अस्थायी खोने से बचाना था। अप्रैल 2024 में इस सुविधा को अस्थायी रूप से फिर शुरू किया गया। उसी साल दिसंबर में इसे अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। पत्र नियम के तहत आवेदकों की कई श्रेणियों के लिए यह सुविधा समाप्त कर दी गई

है। इनमें स्टेटस में बदलाव के लिए आवेदन करने वाले लोग, एच-4 वीजा धारक जीवनसाथी, शरण मांगने वाले आवेदक, शरणार्थी, शरण प्राप्त कर चुके लोग और अस्थायी संरक्षित दर्जा यानी टीपीएस के लाभार्थी शामिल हैं।

इस बदलाव का असर एच-1बी वीजा धारकों के उन जीवनसाथियों पर पड़ सकता है, जो एच-4 वीजा पर अमेरिका में रहते हैं और नैकरी करने के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज यानी ईएडी पर निर्भर हैं। यदि उनके मौजूदा ईएडी की अवधि नवीनीकरण आवेदन मंजूूर होने से पहले समाप्त हो जाती है, तो उन्हें नया वर्क परमिट मिलने तक काम रोकना पड़ सकता है। हालांकि, सभी विदेशी कर्मचारियों पर इसका एक जैसा असर नहीं होगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी एस्पटीइएम विषयों से जुड़े क्षेत्रों में काम करने के लिए रोजगार प्राधिकरण की अवधि बढ़ाने वाले एच-1 छत्र पहले की तरह 180 दिन की ऑटोमैटिक एक्सपैरेशन सुविधा के पात्र बने रहेंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना होगा। एल और ई श्रेणी के वीजा धारकों के जीवनसाथियों को भी राहत मिली हुई है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केटी जकारिया सिर्फ पांच दिन में पद से बाहर

वाशिंगटन , एजेंसी। केटी जकारिया अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नहीं रहेंगी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस पद पर सिर्फ पांच दिन काम किया, जो माना जा रहा है कि इस पद पर किसी भी व्यक्ति का सबसे छोटा कार्यकाल है। जांच एंगपन ने राष्ट्रपति के सलाहकारों के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पद से हटा दिया। वहीं, एनबीसी न्यूज ने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से कहा कि जकारिया को ‘नई भूमिका’ दी जा रही है, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। यह खबर उस दिन सामने आई जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस से खाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जकारिया से पूछा था कि क्या वह इस पद पर बने रहना चाहती हैं।

ट्रंप ने कहा, ‘केटी के साथ मीडिया ने बहुत बुरा व्यवहार किया है, बहुत ही अनुचित तरीके से। मैंने अभी उससे इस बारे में बात की है।’ उन्होंने बताया कि ‘मैंने उनसे कहा, ‘केटी, अगर तुम यह

काम नहीं करना चाहती तो तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘यह उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है।’ मैंने कहा, ‘ट्रंप की दुनिया में आपका स्वागत है।’ अब मैं उन्हें खुद फैसला करने दूंगा। जकारिया ने 12 अक्टूबर को यह पद संभाला था। वे पहले एक कंजर्वेटिव कमेंटेटर और ‘ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप’ में वरिष्ठ संचार सलाहकार रह चुकी हैं। उन्होंने 13 अक्टूबर को अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग की थी। ट्रंप ने 8 अक्टूबर को उन्हें करोलिन लीविट की जगह नियुक्त किया था, जिन्होंने अगस्त के अंत में पद छोड़ दिया था।

उनकी पहली ब्रीफिंग 15 मिनट से भी कम समय चली। उसमें उन्होंने बताया था कि ट्रंप ने किम्बली गिलफॉयल से ग्रीस में अमेरिकी राजदूत का पद छोड़ने को कहा है। हालांकि, वह यह नहीं बता सकी कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद किया है या नहीं।



भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निशाना बना रहे हैं। विपक्षी समूहों प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लंदन में रहने वाले एक भारतीय ने आईएनएस से बातचीत में बताया कि इस सभा का उद्देश्य उन कोशिशों का विरोध करना था, जिन्हें वे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश मानते हैं। उन्होंने कहा, ‘आज हम लंदन के

कि ऐसे प्रदर्शनों से, जिनसे विदेशों में देश की छवि खराब हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, ‘आप असल में किस बात का विरोध कर रहे हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर आपको कोई शिकायत है, तो आप अदालतों, यहां तक ​​​​??कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कानूनी व्यवस्था के जरिए न्याय पा सकते हैं। आपके पास सबूत कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि आपका विरोध इसलिए है क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी, उनके नेतृत्व और उनके ऊर्जा सचिव को पसंद नहीं करते हैं। ‘ भारतीय समुदाय के एक अन्य सदस्य ने आईएनएस को बताया कि यह सभा प्रभावशाली और सरकारी प्रक्रिया में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए चुनी गई है।

भारत भवन में उन लोगों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमारी नजर में भारत को बदनाम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवादी होने के नाते, हम उनके कामों का जवाब देने और अपने देश के बचाव में आवाज उठाने के लिए एक साथ आए हैं। भारत सरकार का विरोध करने वालों के तरीके पर सवाल उठाते हुए, वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि लोकतंत्र में शिकायतों का समाधान कानूनी और संवैधानिक तरीकों से होना चाहिए, न

थीं भेजी गई है। न तो यह प्रमाणित और न ही वह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। दबाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, विदेश मंत्री, टेजरी सचिव और ऊर्जा सचिव के साथ मिलकर, ‘रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात और खरीद से जुड़ी स्थितियों पर नजर रखेंगे।’ साथ ही, वे ‘राष्ट्रपति को तुरंत ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में सूचित करेंगे, जो उनकी राय में यह संकेत दे सकती है कि राष्ट्रपति को आगे कोई कदम उठाने की जरूरत है जिसमें छूट से जुड़े मामले भी शामिल हैं। ‘ व्यापार प्रतिनिधि को राष्ट्रपति को यह भी बताना होगा कि ‘कौन से देश उन

शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं’ जो रूस पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। यह आदेश रूस पर लगे मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंधों को बरकरार रखता है। इसमें कहा गया है कि ‘किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश से रूस के संबंध में जारी किसी भी कार्रवाई आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों या अन्य उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, इस कानून के तहत राष्ट्रपति के पास मौजूद ज्यादातर शक्तियां (जिनमें छूट देने का अधिकार भी शामिल है) अब विदेश मंत्री, टेजरी सचिव, व्यापार प्रतिनिधि और ऊर्जा सचिव को सौंप दी गई हैं।

भारत को मिली राहत, ट्रंप ने रूसी तेल पर लगने वाला शुल्क हटाया

वाशिंगटन , एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वालों को निशाना बनाने वाले एक नए अमेरिकी कानून के तहत शुल्क (टैरिफ) लागू किए, लेकिन साथ ही उसी आदेश में उन्हें माफ भी कर दिया। इससे भारत और चीन जैसे देशों को 100 प्रतिशत शुल्क लगाने से राहत मिल गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ये शुल्क लागू होने में बस एक दिन बचा था और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। शुक्रवार को हस्ताक्षरित और उसी दिन देर शाम व्हाइट हाउस द्वारा जारी इस कार्यकारी आदेश में ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनस रशिया एंड ईरान एक्ट 2026’ को लागू किया गया

है। ट्रंप ने इस कानून पर 18 सितंबर को हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों से आने वाले सामानों पर 30 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान था। यह समय-सीमा रविवार 18 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी। यह आदेश ‘रूसी संघ से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात करने वाले शीर्ष 5 देशों’ के सामानों पर 100 प्रतिशत शुल्क बढ़ाता है, बशर्ते ‘वह देश 18 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद जानबूझकर रूसी संघ से कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस की किसी भी शुल्क को लागू करने से छूट देता हूं (माफ करता हूं)।’ यह आदेश विदेशी व्यक्तियों पर लगाए



देशों’ के सामानों पर भी 100 प्रतिशत शुल्क बढ़ाता है, और रूस से आने वाले सामानों पर शुल्क को 500 प्रतिशत तक बढ़ा देता है। इस आदेश की धारा 4 इन उपायों को तुरंत निलंबित कर देती है। ट्रंप ने लिखा, ‘मैं इसके द्वारा ग्राहम एक्ट की धारा 112 और 113, या इस आदेश में बताए गए किसी भी शुल्क को लागू करने से छूट देता हूं (माफ करता हूं)।’ यह आदेश विदेशी व्यक्तियों पर लगाए

गए कानून के अधिकांश प्रतिबंधों को भी हटा देता है जिसमें इस एक्ट की धारा 102, 102(ख), 102(५), 103 से 111 और 117 शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि ये छूटें ‘तब तक लागू रहेंगी, जब तक कि राष्ट्रपति या विदेश मंत्री, टेजरी सचिव और व्यापार प्रतिनिधि के साथ उचित परामर्श करके यह तय न कर लें कि आगे कोई और कदम उठाना जरूरी है।’ इस आदेश में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को कानून के अनुसार जरूरी लिखित प्रमाणन भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि ‘इस तरह की छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है।’ इसके साथ ही, ‘इस प्रमाणन का

आधार बताने वाली एक रिपोर्ट’ भी भेजी गई है। न तो यह प्रमाणित और न ही वह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। दबाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, विदेश मंत्री, टेजरी सचिव और ऊर्जा सचिव के साथ मिलकर, ‘रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात और खरीद से जुड़ी स्थितियों पर नजर रखेंगे।’ साथ ही, वे ‘राष्ट्रपति को तुरंत ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में सूचित करेंगे, जो उनकी राय में यह संकेत दे सकती है कि राष्ट्रपति को आगे कोई कदम उठाने की जरूरत है जिसमें छूट से जुड़े मामले भी शामिल हैं। ‘ व्यापार प्रतिनिधि को राष्ट्रपति को यह भी बताना होगा कि ‘कौन से देश उन

शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं’ जो रूस पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। यह आदेश रूस पर लगे मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंधों को बरकरार रखता है। इसमें कहा गया है कि ‘किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश से रूस के संबंध में जारी किसी भी कार्रवाई आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों या अन्य उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, इस कानून के तहत राष्ट्रपति के पास मौजूद ज्यादातर शक्तियां (जिनमें छूट देने का अधिकार भी शामिल है) अब विदेश मंत्री, टेजरी सचिव, व्यापार प्रतिनिधि और ऊर्जा सचिव को सौंप दी गई हैं।

गोवा में सीजेपी के प्रदर्शन में हिंदुत्व मुर्दाबाद नारों पर एफआईआर

पणजी (एजेंसी)। गोवा में विपक्षी कॉंग्रेसव जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद जैसे कथित हिंदू विरोधी नारे लगाने के आरोप में 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पणजी पुलिस ने 11 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 196 और 299 के तहत मामला दर्ज किया है। पाजजी के पुलिस इन्स्पेक्टर विजयकुमार चोडनकर ने इसकी पुष्टि कर बताया कि इन नारों से धार्मिक असंतोष फैला और जानबूझकर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। उनका आरोप है कि एसआईआर (एसआईआर) में हेराफेरी की गई है और देश की मजदूतारी सूची से नाम हटाए गए हैं। इस घटना पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कड़ी प्रतिक्रिया देकर कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं होगी और घटना की जांच जारी है। तलेझाओ निवासी रामप्रसाद कैलकर ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए 11 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के एक वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई। कैलकर ने अपनी शिकायत में कहा कि सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नॉर्थ गोवा कलेक्टर द्वारा खारिज कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने हिंदू विरोधी नारे लगाए, जिससे समाज में शांति और सद्भाव भंग करने की कोशिश की गई। इसी प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन की अनुमति न होने के बावजूद आजाद मेदान में घुसने पर पुलिस ने सात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में बीजेपी हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के बाद देर शाम रिहा कर दिया गया था।

राखी सावंत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट : 16 साल पुराने मामले में मुश्किल बढ़ी

झांसी (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत के लिए एक पुरानी मुश्किल फिर खड़ी हो गई है। झांसी की एक जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला 16 साल पुराना है और एक इसतरह के व्यक्ति की कथित आत्महत्या से जुड़ा है, जो नवंबर 2010 में राखी सावंत के टीवी शो राखी का इंसफ़ा में शामिल हुआ था। अदालत ने राखी के कई बार बुलाने के बावजूद पेश न होने पर यह वारंट जारी किया है। प्रेम नगर, झांसी निवासी लक्ष्मण अहिरवार नामक यह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद सुलझाने के लिए शो में आया था। आरोप है कि शो के दौरान राखी ने लक्ष्मण को नामर्द कहकर संबोधित किया था। इस घटना के बाद लक्ष्मण ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। जिला सरकार की वकील (अपराध) मुदुल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

पंजाब के किसानों ने 7 दिसंबर को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने का किया ऐलान

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में किसान फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। किसानों की ओर से 7 दिसंबर को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के संगठन ने चंडीगढ़ कूच करने का ऐलान किया है। पंधेर का कहना है कि सरकार के साथ कई दौर की बैठकें होने के बावजूद उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। किसानों के इस ऐलान के बाद अब सबकी नजर 7 दिसंबर पर टिकी है। देखा होगा कि इससे पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई सहमति बनती है या किसान चंडीगढ़ में अपना मोर्चा खोलते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान नेता पंधेर का कहना है कि सरकार के साथ कई बैठकें होने के बावजूद उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसी के विरोध में किसानों ने चंडीगढ़ में धरना लगाने का फैसला किया है। किसानों की प्रमुख मांगों में 5 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देना शामिल है। किसान संगठनों का कहना है कि फसलों के उचित दाम और अन्य मांगों को लेकर वे लंबे समय से सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

बाजा कैलिफोर्निया तट पर नौका हदसा : 11 लापता, 16 बचाए गए

बाजा (एजेंसी)। बाजा कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में एक नौका पलटने से 11 लोग लापता हो गए हैं। इस हादसे में शुक्रवार को 16 लोगों को बचाया गया, जिसमें मैक्सिको के नागरिक शामिल हैं। बचाए गए लोगों में एक व्यक्ति शार्क के काटने से घायल हो गया था, जिसका इलाज जारी है। जीवित बचे लोगों ने अधिकारियों को बताया कि नौका पर कुल 27 लोग सवार थे। अमेरिकी तटरक्षक बल, नौसेना और मेक्सिको की नौसेना लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। कई विमानों और नौकाओं से समुद्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तटरक्षक बल के अनुसार, इस घटना तटकरों के अवसर सक्रिय रहने वाले क्षेत्र में हुई, लेकिन अमेरिकी जलक्षेत्र में नहीं। तटरक्षक बल के चाली वैलोर ने शनिवार को कहा, हम मदद कर सकते थे और इसी वजह से हमने अपने संसाधनों को इस अभियान में लगाया। शनिवार को एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर भी अभियान में लगाया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह 20 अक्टूबर को पंजाब दौरे पर, नशा पीड़ितों के परिवारों से मिलने का कार्यक्रम

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पोस्ट कर बताया

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अक्टूबर को चुनावी राज्य पंजाब का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे राज्य में नशे की समस्या से जां गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिल सकते हैं। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने घोषणा कर कहा कि केंद्रीय मंत्री शाह के मानसा और संगरूर जाने की संभावना है।

भाजपा नेता बिट्टू ने एक्स पर शाह के दौरे की जानकारी साझा कर पंजाब में नशे के गंभीर खतरे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य को नशे की समस्या से निकालने के लिए निर्णायक कार्रवाई, मजबूत नेतृत्व और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पर जोर दिया। बीजेपी नेता बिट्टू ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार अपना जनादेश खो चुकी है और लोगों से भाजपा के नशामुक्त पंजाब अभियान का समर्थन करने की अपील की।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह



मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। जिनकी 13 अक्टूबर को एक मेडिकल स्टोर मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोप है कि झोटा ने एक बुजुर्ग को मादक पदार्थ बेचने पर सवाल उठया था। झोटा के परिजन अभी भी न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके शव का

अंतिम संस्कार नहीं हुआ है।

इस तरह, केंद्रीय मंत्री शाह संगरूर जिले के दिड़वा में गुलजार सिंह के परिवार से भी मिलने वाले हैं। जिन्होंने 7 सितंबर को आत्महत्या की थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें इलाके में नशीले पदार्थों की आपूर्ति को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल करने पर परेशान किया

और जातिसूचक टिप्पणियां की गई।

केंद्रीय मंत्री शाह ने 16 अक्टूबर को कहा था कि केंद्र इन दोनों घटनाओं को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगेगा। यह 20 दिन के भीतर शाह का पंजाब का दूसरा दौरा होगा। इसके पहले, 30 सितंबर को उन्होंने जालंधर में भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के समापन पर रैली को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने आप सरकार पर चिष्टा (सिंथेटिक नशीले पदार्थ) के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। शाह ने वादा किया था कि यदि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है, तब दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बना दिया जाएगा। उन्होंने जालंधर दौरे में भी नशे से प्रभावित कुछ परिवारों से मुलाकात की थी। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दल नशे की समस्या को लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं।

मधेपुरा गांव का बड़ा फैसला: नशा बेचा या किया तो लगेगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

मधेपुरा, एजेंसी।

बिहार के मधेपुरा गांव वालों ने सिर्फ नशा बेचने वालों को ही नहीं, नशा करने वालों को भी चेतावनी दी है। पंचायत की बैठक में तय हुआ कि अगर कोई नशा करते या बेचते पाया गया तो उस पर 25 हजार रुपए का सामाजिक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी जाएगी, ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सके। ग्रामीणों ने यह संकल्प भी लिया कि अगर कोई नशे के मामले में जेल जाता है, तो उसके परिवार वाले उसकी जमानत नहीं कराएंगे। यह फैसला मधेपुरा सदर प्रखंड की सहृदढ़ पंचायत में लिया है।

जानकारी के मुताबिक सहृदढ़ के स्कूल परिसर में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुखिया मुकेश कुमार ने की। इसमें वर्तमान और पूर्व मुखिया समेत दोनों पंचायतों के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने मिलकर सहृदढ़ को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। अब सवाल है कि पंचायत ने ऐसा फैसला

क्यों लिया? इसे लागू कैसे किया जाएगा? और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने या जमानत नहीं कराने का फैसला कितना कानूनी है? ग्रामीणों का कहना है कि नशे के खिलाफ सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गांव के लोगों को मिलकर इस पर रोक लगाने की कोशिश करनी होगी। बैठक में मौजूद ग्रामीण प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया और गांव के लोगों ने साथ बैठकर यह फैसला लिया गया है उनका कहना था कि आज से सहृदढ़ में नशा बंद कराने की दिशा में सामूहिक कोशिश की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगेगा।

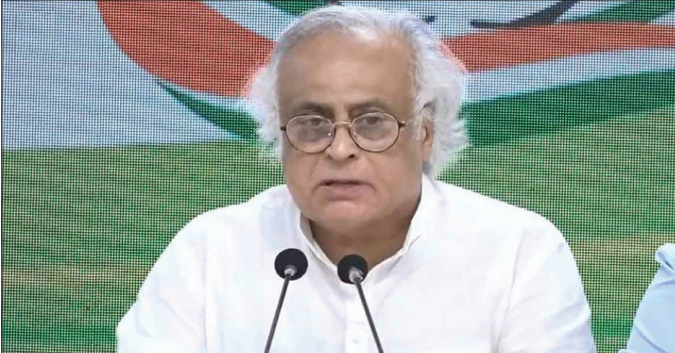
इस फैसले का दूसरा हिस्सा और भी खास है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर नशे के मामले में पकड़ा गया कोई व्यक्ति जेल जाता है, तो उसके परिजन उसकी जमानत कराने के लिए आगे नहीं आएंगे। पंचायत के लोगों को उम्मीद है कि जुर्माने और सामाजिक बहिष्कार जैसी चेतावनी से नशे के खिलाफ माहौल बनाया जा सकेगा।

कांग्रेस ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर को रोकने की मांग की

नई दिल्ली, एजेंसी।

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को 'पढ़ने योग्य' प्रारूप में मतदाता सूची उपलब्ध कराने के फैसले के बीच कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को तत्काल रोकने की अपनी मांग उठाई है। कांग्रेस ने 'वोट चोरों' के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों का परिणाम बताया है।

पार्टी महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बीते दो वर्ष से निर्वाचन आयोग से डिजिटल प्रारूप में मतदाता सूचियां उपलब्ध करने की मांग कर रहे थे, हमारी इस सही मांग को आयोग हर बार ठुकराता रहा। कांग्रेस नेता रमेश ने



बताया कि 2018 में जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लाखों फर्जी मतदाता पकड़े थे, तभी चुनाव आयोग ने 'डिजिटल' मतदाता सूचियां देना बंद किया था, जिससे 'वोट चोरी' को संभव बनाया जा सके। उन्होंने मौजूदा फैसले को वोट चोरों के खिलाफ

सड़कों पर उतरे पूरे देश की जीत बताया। रमेश ने आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों पर काम कर रहे हैं, जिससे निर्वाचन आयोग पर जनता को भरोसा पूरी तरह खत्म हुआ है। उन्होंने

कहा कि ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ना होगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्वाचन आयोग और उसकी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली में पूर्ण बदलाव आवश्यक है। कांग्रेस ने एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की, यह चेतावनी देकर कि यह 13 करोड़ से अधिक भारतीयों के मतदान के सवैधानिक अधिकार को खतरे में डाल सकता है। ज्ञात हो कि निर्वाचन आयोग ने अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश दिया है, जिसकी अंतिम सूचियां 4 जनवरी को प्रकाशित की जाएंगी।

कोलकाता के चोरबागान में भगदड़ के बाद कड़े कदम: 19 मौतों पर प्रशासन अलर्ट

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए

कोलकाता, एजेंसी।

प्रश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भीषण भगदड़ के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है, जिसमें 19 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मरने वालों में 13 महिलाएं शामिल हैं, और हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। भगदड़ के मद्देनजर, कोलकाता पुलिस ने चोरबागान पंडाल के आसपास और उत्तर व मध्य कोलकाता के कुछ सटे इलाकों में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत कार्यक्रम स्थल के पास सड़कों पर लोगों के एकत्रित होने पर पूरी तरह से रोक है। यह प्रतिबंध 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

पश्चिम बंगाल के अग्निशमन मंत्री कौशिक चौधरी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लेकर बताया कि हालात पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। स्वयं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और जल्द ही उच्चस्तरीय बैठक करने वाले हैं। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल को सील किया गया है, जहां फॉरेंसिक टीम, पुलिस



और एमकल विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। पुलिस और अग्निशमन अधिकारी अब दूसरे दुर्गा पूजा पंडालों में भी सुरक्षा-व्यवस्था की जांच कर रहे हैं ताकि ऐसी घटना फिर न हो। मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है। एक अधिकारी ने बताया कि लापरवाही सामने आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस दर्दनाक घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

हादसे में जान गंवाने वाले 19 लोगों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, जो घटना की भयावहता को दिखाता है। सुवेंदु सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे और एक सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। वहीं, घायलों को मुफ्त इलाज के साथ 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है, जिससे पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिल सके।

महाराष्ट्र सूखा संकट: अधिकारी, नेता और सरकार बने किसानों का सहारा

मुंबई , एजेंसी।

महाराष्ट्र के कई हिस्से इस समय गंभीर जल संकट और भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं, इससे राज्य के किसानों की मार आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। इस विकट स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार, सभी एकजुट होकर सामने आए हैं। राज्य के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने संकट से जूझ रहे किसानों की सहायता करने का संकल्प लिया है। इसके तहत, सभी अधिकारी अक्टूबर 2026 के अपने

एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने वाले हैं। इस संबंध में राज्य सरकार को आधिकारिक पत्र भी सौंपा जा चुका है, जो उनके एकजुट समर्थन को दर्शाता है। जनप्रतिनिधि भी इस राहत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। चिपलून-संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शेखर निकम ने अपने एक महीने के मूल वेतन का चेक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सौंप दिया है। वहीं, विधायक रोहित पवार ने महायुति सरकार से यह मांग की है कि सूखा प्रभावित किसानों को प्रति

हेक्टेयर कम से कम 50,000 रुपये और कृषि मजदूरों को तत्काल प्रभाव से 25,000 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करें, ताकि वे इस मुश्किल समय में कुछ राहत पा सकें। महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग ने 14 अक्टूबर, 2026 को राज्य के 305 तालुकों को आधिकारिक तौर पर सूखा प्रभावित घोषित किया है। प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए महायुति सरकार ने कई महत्वपूर्ण रियायतों का ऐलान किया है। इसमें सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को भू-राजस्व से पूरी तरह से छूट, फसल

ऋणों का पुनर्गठन और सभी प्रकार के कृषि ऋणों की वसूली पर तत्काल रोक शामिल है। इसके अतिरिक्त, कृषि पंपों के मौजूदा बिजली बिलों पर विशेष छूट दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों की परीक्षा फीस भी माफ की गई है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो। यह सामूहिक प्रयास संकटग्रस्त किसानों और उनके परिवारों को उम्मीद और समर्थन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



आरोपी का हाफ एनकाउंटर भी किया था। इन घटनाओं पर सभी राजनीतिक दलों ने चिंता व्यक्त करते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी। पप्पू यादव खुदा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे, इस इंचानियत, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे का प्रतीक बताया जाता है। उन्होंने मंच से देश की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की, लेकिन उनके मुख्य संदेश का केंद्रबिंदु महिलाओं की सुरक्षा और छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ उनकी कड़ी चेतावनी थी।